of another firm engaged in manufacture and supply of the same item, Chief Adviser (Cost) recommended wage escalation, worked out on the basis of actual date rather than adoping 0.1 per cent as done earlier. Both the methods of arriving at wage escalation are provided in the contract agreement. After examining the entire issue the Ministry of Railways decided that the wage escalation factor should be based on verification of actual data by the Chief Adviser (Cost).

बगहा और छितौनी के बीच पुल का पुनर्निर्माण कार्य

4299. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगहा और छितौनी के बीच पुल के पुनर्निर्माण कार्य पर आने वाली लागत की हिस्सेदारी का क्या प्रावधान है;

(ख) किस राज्य ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी है ; और

(ग) उक्त कार्य का कितना प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) बगहा और छितौनी के बीच रेल-एवं-सड़क पुल की लागत में जल संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों की हिस्सेदारी इस प्रकार रहेगी :

1. भूमि की लागत सहित गाइड बांधों और उनकी सुरक्षा जैसे पानी के बहाव को नियंत्रित करने संबंधी कार्यों की लागत जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 5:3:2 के अनुपात में वहन की जाएगी ।

2. भूमि की लागत सहित रेल-एवं-सड़क पुल के लिए सामान्य उप-संरचना की लागत रेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 2:1:1 के अनुपात में वहन की जायेगी ।

3. रेल पुल अधिरचना और रेलपथ की समूची लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी ।

4. सडक पुल अधिरचना की लागत में उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का बराबर का हिस्सा रहेगा ।

5. भूमि की लागत सहित खादर में दो पहुंच तटबंधों की लागत में रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार का हिस्सा 70% 15% 15% के अनुपात में रहेगा पिचिंग और टर्फिंग की लागत में रेलों और उ० प्र० तथा बिहार की राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 2:1:1 के अनुपात में रहेगी ।

6. खादर के भीतर सड़क का खड़ंजा बिछाने की लागत में दोनों राज्यों सरकारों का हिस्सा बराबर रहेगा, सेतु बंधन और ग्रेड प्रथक्करण, यदि कोई हो, सहित खादर के बाहर की सडक की लागत, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी ।

(ख) किसी भी अन्य सहभागीदार, यथा, जल संसाधन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने अभी तक अपने हिस्से की समूची राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ग) दिसम्बर, 1992 तक 39% ।

Revenue earnings by Railways

4300. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI SUNIL BASU RAY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have exhausted all avenues of revenue earnings and is poised for substantial fare hikes; and

(b) if so, which section is going to be provided with added comforts more — the upper class or the second class passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) and (b) Adjustments in fares has become unavoidable keeping in view the increase in input costs and also the need for generation of additional resources to finance Development plans. Amenities to passengers of all classes are provided according to the norms laid down.

उत्तर प्रदेश में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना

4301. श्री मुहम्मद मसूद खान :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कार्यवाही योजना का प्रथम चरण किस वर्ष से प्रारंभ होकर किस वर्ष तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इसकी प्राथमिकता के मापदंड क्या होंगे;

(ख) कार्यवाही योजना के प्रथम चरण में शामिल पूर्वोत्तर रेलवे के शाहगंज, आजमगढ़ मऊ में उपर्युक्त मापदंडों के अनुसार मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब प्रारंभ होगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, शाहगंज-मऊ रेलवे लाइन पर फूलपुर, फरिहा, सठियांव रेलवे स्टेशनों का दर्जा विभागीय हाल्ट स्टेशन से बढ़ाकर पूर्णरूपेण बी श्रेणी करने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया है जैसा कि कुछ सांसदों द्वारा 18 फरवरी, 1993 तथा 16 मार्च, 1993 को लिखे गए पत्रों में मांग की गई थी तथा जिनके प्रत्युत्तर में मंत्री ने उपर्युक्त तीनों स्टेशनों का दर्जा बढ़ाकर बी श्रेणी करने का आदेश जारी किया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) वर्ष 1992-93 में शुरू किया गया था । चरण-1 के 2000-2001 में पूरा होने की संभावना है, बशर्ते कि आगामी वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों । तरजीह का आधार विभिन्न लाइनों की पारस्परिक परिचालनिक तथा सामरिक प्राथमिकता है ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ।

(ग) फूलपुर, फरिहा और सठियांव "बी" श्रेणी के स्टेशनों के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे परियोजनायें

4302. श्री कामेश्वर पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा वर्षों पूर्व स्वीकृत बहुत सी परियोजनाओं पर अभी तक कोई कार्य प्रारंभ हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं में कुछ तो बिहार से बाहर स्थानान्तरित हो चुकी हैं अथवा स्थानान्तरण की प्रक्रिया में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) बिहार की इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1993-94 के रेल बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और यह कुल खर्च होने वाली राशि का कितना प्रतिशत है ;

(ङ) क्या 1993-94 के रेल बजट में बिहार की किसी नई परियोजना को स्वीकृति देने हेतु कोई प्रावधान किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?